Demand to adopt appropriate policy for the development of villages to restrict migration towards cities

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। देश की समृद्धि का रास्ता गांव से होकर गुज़रता है। जब देश विश्व का सबसे समृद्धशाली देश था, तब देश की 88 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी। यह 1750 तक की स्थिति थी। उस समय विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान करीब 25 प्रतिशत था। जब देश आज़ाद हुआ, तब भी गांवों में देश की आबादी के करीब 82 प्रतिशत लोग रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद गांवों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ तथा उनको बजट में समुचित हिस्सा न मिलने के कारण उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सड़क, मार्केटिंग आदि की उचित सुविधाएं न मिल पाने के कारण लोगों को विवश होकर गांवों से शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। * एक सर्वे में यह भी पता चला है कि गांवों में रहने वाले व्यक्ति 33 रुपए प्रतिदिन पर अपना जीवन-यापन करने को विवश हैं। यदि गांवों में ही उक्त सभी सुविधाएं होतीं तो वह शहरों की ओर पलायन नहीं करता। आज गांवों की स्थिति यह है कि वहां मात्र 62 प्रतिशत लोग रह रहे हैं। गांव में रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं तथा लघु उद्योग तथा हाथ की दस्तकारी को लम्बे समय तक हतोत्साहित किया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः आपने जो लिखकर दिया है, उसी को पढ़ना है। अपनी तरफ से आपको कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो आप बोल रहे हैं, वह record में जाने वाला नहीं है। जो आपने यहां पर लिखकर दिया है, वही record में जाएगा।

श्री विजय पाल सिंह तोमरः महोदय, महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः जो आपने लिखकर दिया है, उसे ही पढ़ लीजिए।

श्री विजय पाल सिंह तोमरः सर, मैं वही पढ़ रहा हूं। देश की समृद्धि और तरक्की के लिए.. जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों के विकास के लिए वही नीति अपनायी जानी चाहिए, जो शहर के लिए है।

Demand for research and translation of Indian classical texts

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित)ः महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ कारणों से अपेक्षित रहा है। मैंने जैसा लिख कर दिया है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं। भारत एक सभ्यताई राष्ट्र है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस दौरान देश में सैकड़ों रचनाएं ऐसी हुई जिसका भूत, वर्तमान और भावी पीढ़ियों, तीनों के लिए महत्व है। यह बौद्धिक विरासत हमारी अमूल्य संपदा है, जो देश में विविधता में एकता का आभार भी है। देश में जिस तरह राष्ट्रवाद पर पश्चिमी दृष्टि थोपी जा रही है, इसके लिए आवश्यक है कि देश की इन रचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो। उन पर शोध को प्रोत्साहित किया जाए। उदाहरण के लिए असम के श्री शंकर देव जी, तमिल के

*Not recorded.

तिरुवल्लुर, महाराष्ट्र के समर्थ रामदास आदि की रचनाओं का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी सहित सभी भारतीय भाषाओं में हो। इसके लिए एक Center of Classical Studies स्थापित किया जाए और इसके चार Regional Centers बनाए जाएं, जिससे देश में विचारों का मौलिक और सहज प्रवाह हो।

यूरोप ने अपने सभी Classical texts को संरक्षित किया है। अनुवाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और Center for Classical Studies की स्थापना करें।

Demand to ensure that MSP reach to the farmers by protecting them from middlemen

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सदन के द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, भारत सरकार ने आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगुना करने के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए हैं। हम सभी जानते हैं कि "किसान सशक्त तो देश सशक्त", "किसान की जेब भारी तो देश की जेब भारी।"

महोदय, इस दिशा में सरकार ने किसानों को खरीफ की 14 फसलों का लागत से डेड़ गुना मूल्य घोषित करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसका किसानों ने हृदय से स्वागत किया है।

परन्तु, मैं इससे सदन के द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि न्यूनतम घोषित मूल्य की जेब तक पहुंचे, इसके लिए सरकार को उचित समय पर कठोर और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है।

मान्यवर, अभी डेढ़-दो माह पश्चात् फसलें मार्केट में आना प्रारम्भ हो जायेंगी, अतः सरकार को व्यापक व तत्काल सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करना अपेक्षित है, आवश्यक है।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि किसानों को सरकारी तंत्र और बिचौलियों के कुचक्र से बचाकर इस संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर वांछित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम घोषित मूल्य हर दशा में मिल सके।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री कैलाश सोनी। आप उसी का वाचन करिए, जो आपने यहां पर लिखकर दिया है।

Demand to build and maintain the service and internal roads for cities along with main roads and over bridges

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सर्विस रोड्ज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि रोड्ज़ निर्माण के मामले में सरकार का कार्य अत्यंत सराहनीय है। सारे देश में गुणवत्ता की रोड्ज़ का निर्माण हो रहा है।